भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. **ŧ2223**

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लए

खानों की नीलामी

ŧ2223. श्री टी.एम.सेल्वागणपति:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या सरकार वर्ष 2031 तक कई खानों की नीलामी करने पर वचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है क यह 16300 करोड़ रुपए के नेशनल क्रटिकल मनरल मशन के लए सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप है;

(ग) क्या नेशनल क्रटिकल मनरल मशन में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा 18000 करोड़ रुपए के निवेश की अलग से परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मशन (एनसीएमएम) के तहत सरकार का लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। 2024-25 से 2030-31 तक मशन अव ध के दौरान 100 से अ धक ब्लॉकों की नीलामी की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के 24 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई है। इस मशन पर 16,300 करोड़ रूपये का व्यय होगा । इसके अतिरिक्त पीएसयू आदि द्वारा 18,000 करोड़ रूपए का निवेश अपे क्षत है।

(ग) और (घ) जी हां । राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मशन में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों आदि द्वारा 18,000 करोड़ रुपये के अलग से निवेश की परिकल्पना की गई है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश कर सकते हैं, वे हैं खनिज बिदेश इं डया ल मटेड (काबिल), कोल इं डया ल मटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय खनिज वकास निगम (एनएमडीसी), एनटीपीसी माइनिंग ल मटेड, नेवेली लग्नाइट कॉर्पोरेशन इं डया ल मटेड (एनएलसीआईएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इं डया (सेल), इं डयन रेयर अर्थ ल मटेड (आईआरईएल), ऑयल इं डया ल मटेड, ओएनजीसी वदेश ल मटेड (ओवीएल)। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी महत्वपूर्ण खनिजों में वदेश में निवेश करने के लए प्रोत्साहित कया जा रहा है।

*****